

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)पीठासीन अधिकारी - तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 024/2021 (रे.वि.) (GCMS 2021/25)	दायर दिनांक 01.01.2021	निर्णय दिनांक 27.10.2021
--	---------------------------	-----------------------------

अनवान

मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय मकराना-रोड, मदनगंज किशनगढ़, जिला अजमेर मुख्यालय-17, ओल्ड फतेहपुरा, उदयपुर (राज.) तथा आर. के. नगर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) जरिये प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

प्रार्थी

बनाम

नारायणलाल पिता दल्ला जाति डांगी निवासी सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अप्रार्थी

उपस्थिति :- अमित नाहर
सीएम जणवा

अधिवक्ता प्रार्थी
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

--: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 (2) एवं (4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी कम्पनी वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में सीमेंट प्लान्ट स्थापित किये जाने एवं एप्रोच रोड हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम रसूलपुरा, सांगरिया, बोराखेडी एवं अहीरपुरा तहसील निम्बाहेडा में स्थित 115.07 बीघा यानि 72.094 हैक्टर भूमि 99 वर्ष की लीज पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान इण्डस्ट्रीयल एरिया अलॉटमेंट रूल्स 1959 के अन्तर्गत प्रदान की। राज्य सरकार द्वारा वण्डर सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 07.01.2009 को लीज डीड निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय, निम्बाहेडा में दिनांक 12.01.2009 को पंजीकृत कराई। प्रार्थी कम्पनी इस भूमि पर सीमेंट प्लान्ट स्थापित कर सीमेंट का उत्पादन करती चली आ रही है। वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा में सीमेंट प्लान्ट लगाने की शर्त पर राज्य सरकार के खान विभाग द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22 (1) के अन्तर्गत लाईम स्टोन(सीमेंट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु ग्राम फलवा, भट्टकोटडी, रसूलपुरा, लसडावन,



(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

माल्याखेडी एवं पीरखेडा की 740.93 हैक्टर भूमि के लिये खनन-पट्टा अनुदान किया है जिसका लीज डीड प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में दिनांक 08.09.2008 को निष्पादित होकर उप पंजीयक कार्यालय निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 11.09.2008 को पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी इस खनन क्षेत्र में अवाप्त की गई भूमि पर खनन कार्य कर रही है। प्रार्थी कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा प्लान्ट हेतु भूमि प्रदत्त की गई एवं माईनिंग लीज प्रदत्त की गई भूमि के मध्य ग्राम सांगरिया तहसील निम्बाहेडा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 की कृषि भूमि स्थित है जिसके वर्तमान में इस कृषि भूमि के तहसील निम्बाहेडा द्वारा नवीन भू-माप हो जाने से खसरा नम्बर 18 के नवीन खसरा नम्बर 21 है। प्रार्थी की राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि एवं माईनिंग लीज के मध्य विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाजी की भूमि ग्राम सांगरिया के खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 21 का क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टर में स्थित है। इस कृषि भूमि के कुलिया क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टर भूमि प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज क्षेत्र में सीमेंट प्लान्ट में कच्चा माल लाने हेतु कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विपक्षी के खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 का क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टर में स्थित है। इस कृषि भूमि के कुलिया क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टर कृषि भूमि की प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज क्षेत्र में सीमेंट प्लान्ट में कच्चा माल लाने हेतु कन्वेयर बेल्ट लगाने हेतु आवश्यकता है। विपक्षी की खातेदारी की कृषि भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी को कच्चा माल लाने हेतु कन्वेयर बेल्ट के अभाव में प्लान्ट को उपलब्ध नहीं हो सकेगा, प्रार्थी कम्पनी को कन्वेयर बेल्ट लगाने के प्रयोजनार्थ विपक्षी की कृषि भूमि जो प्रार्थी कम्पनी की स्वीकृत माईनिंग लीज व प्लान्ट के समीप स्थित होने से आनुषांगिक कार्य हेतु कन्वेयर बेल्ट हेतु विपक्षी की भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः विपक्षी की प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) एवं (4) के अन्तर्गत कन्वेयर प्रयोजनार्थ अवाप्त किया जाना न्यायोचित है। विपक्षी की प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी के सीमेंट प्लान्ट की बाउण्ड्री से लगी हुई है एवं ग्राम रसूलपुरा, भट्टकोटडी को स्वीकृत माईनिंग लीज के बाउण्ड्री लाईन के समीपस्थ स्थित है। प्रार्थी कम्पनी की ग्राम रसूलपुरा, भट्टकोटडी, फलवा से कच्चा माल लाने ले जाने के लिये कन्वेयर बेल्ट हेतु आनुषांगिक कार्य हेतु आवश्यकता होने से प्रार्थी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (2) एवं (4) के अन्तर्गत विपक्षी की कृषि भूमि की मुआवजा राशि निर्धारण कराने का अधिकारी है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के अनुसार प्रार्थी कम्पनी विपक्षी को कृषि भूमि की मुआवजा राशि अदा करने हेतु तत्पर एवं तैयार है। प्रार्थी कम्पनी को प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि की कन्वेयर बेल्ट प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। उक्त कृषि भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी के सीमेंट प्लान्ट हेतु कच्चा माल लाने एवं ले जाने के कार्य पर विपरित प्रभाव होगा। अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि की मुआवजा राशि प्राप्त कर विपक्षी अन्यत्र कृषि भूमि प्राप्त कर सकेंगे। विपक्षी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (2) एवं (4) के



(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अन्तर्गत अवाप्त किया जाना न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है सो स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम सांगरिया तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित विपक्षी की खातेदारी की कृषि भूमि के कुलिया क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टर की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर अवाई पारित फरमाया जावे। विपक्षी को मुआवजा राशि का भुगतान कर भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे तथा राजस्व अभिलेख में उक्त कृषि भूमि को सीमेंट प्लान्ट की कन्वेयर बेल्ट हेतु वण्डर सीमेंट लिमिटेड मकराना रोड, मदनगंज-किशनगढ़ जिला अजमेर के नाम पर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

इस पर प्रार्थी कम्पनी के प्रार्थना-पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना-पत्र के तलब किया गया एवं उप-पंजीयक निम्बाहेडा से उक्त ग्राम की सिंचित/असिंचित कृषि भूमि की सड़क के पास अथवा दूर आबादी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा से आराजीयात जैरबहस के संबंध में आबादी से दूरी की स्थिति, भूमि में स्थित संरचना, निर्माण, वृक्ष, पत्थर कोट आदि की मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट के निर्देश दिये गये।

दिनांक 31.08.2021 को अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता सीएम जणवा हाजिर आये एवं अधिकार पत्र एवं इकबालिया जवाब प्रार्थना पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/पंजीयन/2021/234 दिनांक 16.08.2021 से ग्राम सांगरिया तहसील निम्बाहेडा की कृषि भूमि की वर्तमान प्रचलित बाजार दर प्रति हैक्टर प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/राजस्व/2021/ 664 दिनांक 27.08.2021 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट दिनांक 13.08.2021 प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 27.10.2021 को उभयपक्ष अधिवक्तागण हाजिर आये एवं बहस पत्रावली हेतु निवेदन किया जाकर प्रकरण का आज ही निस्तारण किये जाने की ईशतदुआ की गई। इस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ में सीमेंट प्लान्ट स्थापित किये जाने एवं एप्रोच रोड हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम रसूलपुरा, सांगरिया, बोराखेडी एवं अहीरपुरा तहसील निम्बाहेडा में स्थित 115.07 बीघा यानि 72.094 हैक्टर भूमि 99 वर्ष की लीज पर राज्य सरकार द्वारा राजस्थान इण्डस्ट्रीयल एरिया अलॉटमेंट रूल्स 1959 के अन्तर्गत प्रदान की। राज्य सरकार द्वारा वण्डर सीमेंट लिमिटेड के पक्ष में दिनांक 07.01.2009 को लीज डीड निष्पादित कर उप पंजीयक कार्यालय, निम्बाहेडा में दिनांक 12.01.2009 को पंजीकृत कराई। वण्डर सीमेंट लिमिटेड को तहसील निम्बाहेडा में सीमेन्ट प्लान्ट लगाने की शर्त पर राज्य सरकार के खान विभाग द्वारा प्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1960 के नियम 22 (1) के अन्तर्गत लाईम स्टोन(सीमेंट ग्रेड) की आपूर्ति हेतु ग्राम फलवा, भट्टकोटडी, रसूलपुरा, लसडावन, माल्याखेडी एवं पीलखेडा की 740.93 हैक्टर भूमि के लिये



3
(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

खनन-पट्टा अनुदान किया है जिसका लीज डीड प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में दिनांक 08.09.2008 को निष्पादित होकर उप पंजीयक कार्यालय निम्बाहेडा द्वारा दिनांक 11.09.2008 को पंजीयन की गई है। प्रार्थी कम्पनी को राज्य सरकार द्वारा प्लान्ट हेतु भूमि प्रदत्त की गई एवं माईनिंग लीज प्रदत्त की गई भूमि के मध्य ग्राम सांगरिया तहसील निम्बाहेडा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 की कृषि भूमि स्थित है जिसके वर्तमान में इस कृषि भूमि के तहसील निम्बाहेडा द्वारा नवीन भू-माप हो जाने से खसरा नम्बर 18 के नवीन खसरा नम्बर 21 है। प्रार्थी की राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त भूमि एवं माईनिंग लीज के मध्य विपक्षी की खातेदारी एवं कब्जेयाजी की भूमि ग्राम सांगरिया के खाता संख्या 179 के खसरा नम्बर 21 का क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टेयर में स्थित है। इस कृषि भूमि के कुलिया क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज क्षेत्र में सीमेंट प्लान्ट में कच्चा माल लाने हेतु कन्वेयर बेल्ट स्थापित करने हेतु आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित विपक्षी के खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 21 का क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टेयर में स्थित है। इस कृषि भूमि के कुलिया क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टेयर कृषि भूमि की प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज क्षेत्र में सीमेंट प्लान्ट में कच्चा माल लाने हेतु कन्वेयर बेल्ट लगाने हेतु आवश्यकता है। विपक्षी की खातेदारी की कृषि भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी को कच्चा माल लाने हेतु कन्वेयर बेल्ट के अभाव में प्लान्ट को उपलब्ध नहीं हो सकेगा, प्रार्थी कम्पनी को कन्वेयर बेल्ट लगाने के प्रयोजनार्थ विपक्षी की कृषि भूमि जो प्रार्थी कम्पनी की स्वीकृत माईनिंग लीज व प्लान्ट के समीप स्थित होने से आनुषांगिक कार्य हेतु कन्वेयर बेल्ट हेतु विपक्षी की भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इस पर विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी की कृषि भूमि की मुआवजा राशि स्वरूप वर्तमान में प्रचलित बाजार दर (Market Value) एवं अन्य देय परिलाभों के साथ उचित मुआवजा राशि दिलाई जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि कृषि भूमि के अभाव में प्रार्थी कम्पनी के सीमेंट प्लान्ट हेतु कच्चा माल लाने एवं ले जाने के कार्य पर विपरित प्रभाव होगा। अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 (2) एवं (4) के अन्तर्गत अवाप्त की जाकर विपक्षी की खातेदारी की कृषि भूमि के कुलिया क्षेत्रफल 0.2100 हैक्टेयर की मुआवजा राशि का निर्धारण कराया जाकर अवार्ड पारित फरमाया जावे। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। सुनी गई बहस के तथ्यों पर चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिवर्ज की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। हमने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के प्रावधानों का अवलोकन किया।



53
(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

89 Right of minerals, mines, quarries and fisheries –

- 1 The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall, have all powers necessary for the enjoyment of such a right.
- 2 The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purposes subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. The staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.
- 3 If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub-sections (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions and reservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned:
Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land effected and their objection have been heard and considered.
- 4 If, in the exercise of the right herein referred over any land, the rights of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the State Government or its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, or, if this award is not accepted, by the civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).
- 5 No assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed.
- 6 If any assignee of the State Government fails to pay compensation as provided in sub-section (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the person entitled to it, as if it were an arrear of land revenue.
- 7 Any person who without lawful authority extracts or removes minerals from any mine or quarry, the right to which vests in and has not been assigned by the State Government, shall without prejudice to any other section that may be taken against him liable, on the order in writing of the Collector to pay a penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed:
Provided that if the sum so calculated is less than one thousand rupees, the penalty may be such larger sum not exceeding one thousand rupees as the Collector may impose.

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रार्थना पत्र की क्षेत्राधिकार इस



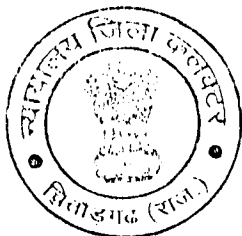
53
(लारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पोषणीय पाया है। अधिनियम की धारा 89 (2) के अनुसार सभी खानों और खदानों के अधिकार में खनन और उत्खनन के उद्देश्य के लिए भूमि तक पहुंच का अधिकार और कार्यालयों, कामगारों के आवास और मशीनरी के निर्माण सहित अन्य सहायक भूमि पर कब्जा करने का अधिकार शामिल है। खनिजों को जमा करना और कचरा जमा करना, सड़कों, रेलवे या ट्राम लाइनों का निर्माण, और कोई अन्य उद्देश्य जिसे राज्य सरकार खनन और उत्खनन के लिए सहायक घोषित कर सकती है। इसके साथ अधिनियम की धारा 89 (4) अनुसार किसी भी भूमि पर निर्दिष्ट अधिकार के प्रयोग में, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ऐसी भूमि की सतह के कब्जे या गड़बड़ी से होता है, तो राज्य सरकार या उसका समनुदेशिती ऐसे व्यक्तियों को इस तरह के उल्लंघन के लिए मुआवजे का भुगतान करेगा और ऐसे मुआवजे की राशि की गणना कलक्टर द्वारा की जाएगी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी की कृषि भूमि जो प्रार्थी कम्पनी की स्वीकृत माईनिंग लीज व प्लान्ट के समीप स्थित होने से आनुषांगिक कार्य हेतु कन्वेयर बेल्ट हेतु विपक्षी की भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही अप्रार्थी की और से पत्रावली पर इकबालिया जवाब प्रार्थना-पत्र रिकार्ड पर है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी कम्पनी द्वारा खनन कार्य में अप्रार्थी की कृषि भूमि प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग लीज एरिया में स्थित होकर कम्पनी को उक्त भूमि की खनन प्रयोजनार्थ आवश्यकता होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 89 के तहत प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं अप्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ से भूमि का उचित मुआवजा निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

कृषि भूमि को खनन प्रयोजनार्थ लिये जाने के संबंध में हमने पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी की खातेदारी आराजीयात खसरा नम्बर 21 क्षेत्रफल 0.21 हैक्टेयर कृषि भूमि में स्थित संरचना व उनकी कीमत का विवरण प्रस्तुत किया गया है जो कि निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संरचना विवरण	कीमत संरचना(रुपये में)
1.	वृक्ष	19000/-
2.	नलकूप (2)	100000/-
3.	पाईप लाईन (भूमिगत)	105000/-
संरचनाओं का कुल योग		224000/-

हमने उप पंजीयक निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत की गई इस ग्राम की सिंचित/असिंचित/बीड़ भूमि की आबादी एवं सड़क से पास तथा दूर की जिला दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित दरों का अवलोकन किया। उप पंजीयक द्वारा इस भूमि की उच्चतम सिंचित, सड़क व आबादी के पास की दर 11,23,389/- रुपये प्रति हैक्टेयर होना बताया है, किन्तु हम भूमि का खनन प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग में लिये जाने से जिला दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित दरों की दुगुनी दर



५३
(सारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

22,46,778/-रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि का मुआवजा निर्धारित करना उचित मानते हैं।

ग्राम	आराजी नम्बर	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	मुआवजा हेतु निर्धारित दर प्रति हैक्टेयर (रूपये में)	देय राशि (रूपये में)
सांगरिया	21	0.21	2246778	471824/-
कुल किता - 1		कुल क्षेत्रफल 0.21 हैक्टेयर	कीमत संरचना	224000/-
			योग	695824/-
			100% सोलिशियम	695824/-
			कुल देय राशि	1391648/-
अक्षरे तेरह लाख इकरानवे हजार छः सौ अड़तालीस रूपये मात्र/-				

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89(4) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है एवं उपरोक्त तालिका अनुसार अप्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि का खनन प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु भूमि का मुआवजा निर्धारण किया जाता है। अतः प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त राशि के भुगतान हेतु चेक तहसीलदार, निम्बाहेड़ा को उपलब्ध करावे। तहसीलदार उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के संबंध में सन्तुष्टि के उपरान्त संबंधित को हिस्सानुसार राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। उपरोक्त भूमि खनन एवं आनुषांगिक कार्य करने हेतु उपयोग में लिये जाने से तहसीलदार द्वारा सरफेस रेन्ट राशि प्रार्थी कम्पनी से वसूल कर भूमि को बिलानाम माईनिंग लीज के अन्य आनुषांगिक प्रयोजनार्थ प्रार्थी कम्पनी के नाम अंकन करने के पश्चात प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीजडीड व विभागीय परिपत्रों के तहत भूमि खनन के आनुषांगिक कार्य हेतु उपयोग में ली जा सकेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेड़ा को नियमानुसार पालना बाबत भिजवाई जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 27.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(तारा) चन्द मीणा
जिला कलक्टर,
दिलौड़गढ़